(c) whether Government are aware of the complaints by depositors about the deduction of income tax from the matured value of fixed deposits and thus lowering the rate of interest thereon by Punjab National Bank, Delhi Cantt.; and

(d) if so, what action Government propose to take to ensure that the matured amount is paid to the depositors and also the income tax deducted by the said bank without the knowledge of the depositors may be refunded?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Non-compliance of RBI guidelines

4220. SHRI MOHD. KHALEELUR RAHMAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the nationalised banks are not following the guidelines of Reserve Bank of India in taking accommodation in non-conforming areas to run their branches in Delhi/New Delhi;

(b) whether it is also a fact that the Sheikh Sarai Branch of the United Commercial Bank, is executing their business from different premises due to which customers are facing a lot of inconvenience;

(c) if so, whether they have obtained prior permission from Reserve Bank of India therefor; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (d) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

RBI guidelines on banks premises

4221. SHRI MOHD. KHALEELUR RAHMAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what are the guidelines issued by the Reserve Bank of India for taking private accommodation in non-conforming areas to run different branches of Nationalised Banks in Delhi/New Delhi;

(b) whether these guidelines are in accordance with the Delhi Rent Control Act; and

(c) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (c) The information being collected and will be laid on the table of the House.

Purchase of Reliance shares by financial Institutions

4222. SHRI VISHWASRAO RAMRAO PATIL:

DR. BAPU KALDATE:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that UTI, LIC, GIC and other public sector institutions and mutual fund bought about one crore shares of Reliance Industries after the scam broke out;

(b) whether the average price of shares so bought was over Rs. 300/-;

(c) whether Government are aware that most of these shares belonged to the persons and companies notified by the costodians; and

(d) whether Government are also aware that these shares were bought by these public sector institutions as their top officials, especially of UTI, received huge kickbacks running into several crores of rupees?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) No, Sir. The total number of shares of Reliance Industries purchased by UTI and other mutual funds after 24th April, 1992 as reported by respective institutions amounted to 57,37,510. LIC, GIC and other public sector financial institutions have not reported any purchases.

(b) No, Sir.

(c) Among the above shares, it is reported that only 2.31 per cent of the shares purchased by UTI were found to be belonging to the persons and companies notified by the custodian.

(d) No such information has come to the notice of the Government and UTI has reported that the allegation is totally baseless.

भारत के संबंध में विश्व बैंक की टिप्पणियां

4223. **श्री अनन्त राम जायसवाल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने वर्ष 1992 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भारत में बढ़ती हुई मंहगाई, बेरोजगारी और बढ़ते हुए विदेशी ऋण पर चिन्ता व्यक्त की है ;

(ख) क्या उक्त रिपोर्ट में यह टिप्पणी भी दी गई है कि सरकार के बाजारोन्मुख कार्यक्रमों से निर्धन लोगों को लाभ नहीं होगा ;

(ग) क्या यह सच है कि विश्व बैंक से जून, 1992 तक प्राप्त 1620 करोड़ डालर की कुल सहायता राशि में से सरकार ने 31 अक्टूबर, 1992 तक 657 करोड़ डालर की राशि का प्रयोग नहीं किया था ;

(घ) उपर्युक्त चिन्ता और टिप्पणियों के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ङ) उपर्युक्त चिन्ता और टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए विदेशी ऋण, बेरोजगारी और मूल्य-वृद्धि से निपटने के लिए क्या कोई कार्यक्रम तैयार किए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) वर्ष 1992 की विश्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया है कि सरकार ने वृहत-आर्थिक स्थिरीकरण और संरचनात्मक सुधार के ऐसे बहुत से निर्णायक उपाय किए हैं जिनसे देश का नीतिगत ढांचा मूल रूप से बदल गया है । इसमें व्यापार-उदारीकरण, वित्तीय एवं पूंजी बाजारों में सुधार, शुल्क-पुनर्निर्धारण और उद्यमों हाइड्रोकार्बन, आदि में कई अन्य उपाय शामिल हैं । रिपोर्ट मे, सार्वजनिक उद्यमों के सुधारों से कर्मचारियों पर पड़ने वाले तत्काल प्रभाव को कम करने की दृष्टि से राष्ट्रीय नवीकरण निधि का स्थापना को भी मान्यता दी गई है । रिपोर्ट में यह भी इंगित किया गया है कि कि सरकार को संरचनात्मक उपायों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप अस्थायी रूप से मुद्रा-स्फीती की उच्चतर दर के जोखिम का भी सामना करना होगा और गरीबी कम करने का दीर्घविधिक लक्ष्य एकदम सुधारों की सफलता पर निर्भर करता है चूंकि सतत विकास में इनका योगदान रहता है ।

(ग) से (ङ) जून 1992 में विश्व बैंक से लिए गए ऋणों की कुल राशि 36.787 अरब डालर के समकक्ष थी । 31 अक्टूबर, 1992 तक की अनुपयुक्त राशि 11.609 अरब अमेरिका डालर थी । अनुपयुक्त ऋण की राशि इसलिए अधिक है क्योंकि इसका संवितरण परियोजना संबंधी सम्मत मान्य क्रियाकलापों के लिए औसतन सात वर्षों की अवधि में करना होता है । विश्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में दर्शायी गई चिन्ताओं पर यथोचित्त ध्यान दिया गया है । विदेशी ऋण से परिशोधन, बेरोजगारी और मूल्य वृद्धि में के संबंध में सरकार की नीतियों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है विदेशी सहायता के इस्तेमाल को भी समय-समय पर समीक्षा की जाती है और अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में कार्यान्वयन करने वाले राज्यों को विदेशी सहायता का शत प्रतिशत अंतरित करने अग्रिमों के उपबंध और अतिरिक्त केंद्रीय सहायता की मासिक निकासी द्वारा इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए हाल ही में उपाय किए गए हैं ।